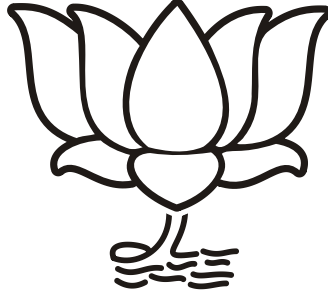


भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव : 2008

चुनाव घोषणा पत्र



आशा भरे उज्ज्वल भविष्य के लिए
भाजपा को वोट दें

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली

29 नवम्बर, 2008 को दिल्ली की 1.75 करोड़ जनता को कांग्रेस के एक दशक के दिशाहीन और भ्रष्ट शासन से निजात पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को वचन देती है कि सत्ता में आने पर वह दिल्ली को विश्वस्तरीय महानगर बनाएगी जिसमें सभी वर्गों, क्षेत्रों और प्रदेशों के लोगों को सद्भाव और सौहार्दपूर्वक रहने और प्रगति करने का समान अवसर उपलब्ध होगा। और यह परिवर्तन होगा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में जिनका राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र का लम्बा अनुभव, बेदाग व्यक्तित्व, प्रशासनिक कौशल, विराट संसदीय अनुभव किसी के लिए भी ईर्ष्या की बात हो सकती है। श्री मल्होत्रा के मुख्य कार्यकारी पार्षद (1967-72) का कार्यकाल दिल्ली के विकास का स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है। इस काल में बहुमुखी और सर्वांगीण विकास की नींव रखी गई। पहली बार फ्लाईओवर बने, भूमिगत मार्ग बने, 18 कालेज खोले गए, यमुना तटों को सुंदर और हरा-भरा बनाया गया, भूमिहीनों को भूमि दी गई, नए अस्पताल और डिस्पेंसरियां खोली गईं और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर नगर बनाया गया। प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया, हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोला गया, गलियों में ईंटों के खड़ंजे और नालियां बनाई गईं, 4 हजार कटरों में फ्लश की टट्टियां बनीं और वहां के निवासियों को शुद्ध जल तथा बिजली प्रदान की गई।

भाजपा शासनकाल की उपलब्धियां

दिल्लीवासियों को स्मरण है कि 1993-98 की अवधि में भाजपा शासन के दौरान दिल्ली के विकास के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे :-

- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एनडीए सरकार ने संसद में विधेयक पेश किया।
- कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया; सुरक्षा का वातावरण प्रदान किया गया।
- दिल्ली को पानी के संकट से उबारने के लिए पड़ोसी राज्यों से ऐतिहासिक जल समझौता किया गया।
- नांगलोई जल शोधन संयंत्र का निर्माण।
- पानी और बिजली के सुप्रबन्धन के लिए दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विद्युत बोर्ड निकायों का गठन।
- प्रशासनिक सुधार के कदम के तौर पर दिल्ली को जिलों और सब-डिजीवनों में बांटा गया
- यमुनापार के विकास के लिए यमुनापार विकास बोर्ड का गठन।
- दिल्ली मेट्रो का शुभारम्भ।
- इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की स्थापना।
- नए कालेज खोले गए।
- पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो का सफल अभियान।
- किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि।
- युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन।
- गो और गोवंश के वध पर प्रतिबन्ध।
- लाटरी पर प्रतिबंध
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रियल पार्क का विकास और उसमें 200 प्लॉटों का आवंटन।

दिल्ली नगर निगम में भाजपा शासन की उपलब्धियाँ

वर्ष 2007 में दिल्ली नगर निगम में भाजपा को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। दिल्ली सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के बावजूद भी अल्पावधि में ही नगर निगम में भाजपा ने निम्नलिखित शानदार उपलब्धियाँ दिखाई :

निगम बजट 2200 करोड़ से बढ़ाकर 2008-09 में 5000 करोड़ किया; ग्रामीण व अनधिकृत कालोनियों को सीलिंग व तोड़फोड़ से बचाया; सम्पत्तिकर के मामले में अनेक रियायतें; गांवों में एक स्वरिहायशी मकान पर हाउस टैक्स माफ; ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत की छूट; महिलाओं/60 वर्ष के वृद्धों को 200 वर्गमीटर तक एक स्वरिहायशी मकान पर सम्पत्ति कर में छूट; पहली बार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निशुल्क; आजाद मार्किट व पंखा रोड पुल सहित दिल्ली में 17 नये पुलों की योजना प्रारम्भ; शहरी इलाकों की सड़कों के निर्माण के लिए भारी राशि का प्रावधान; 24 परम्परागत कार पार्किंग और 16 ऑटोमैटिक कार पार्किंग स्थलों का निर्माण प्रारम्भ; लाइसेंस नीति का सरलीकरण; नई राष्ट्रीय तहबाजारी नीति लागू; बालिकाओं को 200 रुपये प्रति वर्ष वजीफे का प्रस्ताव; विधवाओं की लड़कियों की शादी हेतु 20000 रुपये की सहायता के साथ समुदाय भवन/पार्क निःशुल्क उपलब्ध; प्रत्येक वार्ड में विकलांगों को ट्राइसाइकिल और गरीब महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण; प्रत्येक वार्ड में जिम के लिए 10 लाख रु. और वृद्धों के मनोरंजन केन्द्र के लिए 10 लाख रु. का प्रावधान; 1985 की स्लम योजना में पंजीकृत लोगों को आवास मुहैया कराना; पार्षद फंड में 2 करोड़ रुपये प्रति वार्ड का प्रावधान व ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख का पृथक् प्रावधान।

कांग्रेस के झूठे वायदे

- 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वायदा किया था कि :
- दिल्ली नगर निगम का पुनर्गठन किया जाएगा ।
 - व्यापार एवं व्यवसाय के लिए पृथक् विभाग का गठन किया जाएगा ।
 - दिल्ली की पेयजल क्षमता की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी ।
 - बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई उत्पादन इकाइयों का निर्माण किया जाएगा ।
 - पुनर्वास बस्तियों के लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा ।
 - मार्च 2003 तक बनी अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाएगा ।
 - 50 प्रतिशत प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों वाले क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा ।
 - लाल डोरा बढ़ाया जाएगा ।
 - युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा ।
 - बड़ी संख्या में आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा ।
 - दिल्ली को जनसुविधाओं और पर्यावरण की दृष्टि से विश्वस्तरीय नगर बनाया जाएगा ।
 - दिल्ली को अधिकार सम्पन्न पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा ।
 - भूमि सुधार कानून की धारा 81 को समाप्त किया जाएगा ।

दिल्ली का जागरूक मतदाता कांग्रेस के विगत 10 वर्षों के कुशासन पर नज़र दौड़ाता है तो उसे उक्त वायदे खोखले राजनीतिक नारे प्रतीत होते हैं। दिल्लीवासियों को छलने की कांग्रेस की कुचेष्टा ने आज उसकी विश्वसनीयता ही खो दी है।

कांग्रेसी कुशासन का एक दशक

दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने विगत एक दशक के अपने शासनकाल में दिल्ली को बलात्कार की नगरी, सर्वाधिक प्रदूषित शहर और आतंकवादियों का आसान निशाना बना डाला है। दिल्ली आतंक, असुरक्षा और अव्यवस्था का पर्याय बन गई है।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्लीवासियों के घावों पर नमक छिड़कने और अपने व्यंग्यवाणों से उन्हें छलनी करने का कोई अवसर नहीं चूकतीं। जब टीवी जर्नलिस्ट सौम्या की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे रात के समय गाड़ी ड्राइव करते हुए जाने की क्या जरूरत थी? क्या यह दिल्ली की महिलाओं का अपमान नहीं है? जब दिल्लीवासी बसों से रौंदे जा रहे थे तो अपराधियों को सजा देने के बजाए मुख्यमंत्री दिल्लीवासियों को उपदेश दे रही थीं कि वे बसों पर चढ़ना और सड़कों पर चलना सीखें। उत्तर प्रदेश और बिहार के दिल्ली में रहने वाले लोगों के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियां बताती हैं कि वह आम आदमी के प्रति कितनी असंवेदनशील हैं।

कांग्रेस के शासनकाल के दौरान दिल्ली असुरक्षित नगरी बन गई है। अक्टूबर 2005 से एक-के-बाद-एक अनेक बम ब्लास्ट हो चुके हैं और उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री संसद पर हमले के अपराधी अफ़जल गुरु की फाईल दबाए बैठी हैं। उन्हें दिल्ली की सुरक्षा से ज्यादा चिन्ता अपने वोट बैंक की है। इसीलिए इन्सपैक्टर मोहन चन्द्र शर्मा जैसे शहीदों का अपमान किया जा रहा

है और आतंकवादियों का महिमामंडन।

पर्यावरण के प्रति कांग्रेस की अक्षम्य लापरवाही के कारण यमुना का शुद्धीकरण खटाई में पड़ा हुआ है। दिल्ली के अनेक इलाके बिजली की कटौती की मार झेल रहे हैं। दिल्ली की 35 प्रतिशत आबादी को पेय जल तक मुहैया नहीं। कांग्रेस शासन में बिजली के निजीकरण का जो कदम उठाया गया, उसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं की परेशानियों में वृद्धि हुई है, बिजली के मीटर तेज चल रहे हैं, लेकिन डिस्टिकाम कम्पनियों से सांठगांठ कर चुकी कांग्रेस सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही। सीएजी (CAG) ने भी बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया में हुए घोटाले का निर्देश किया है। सरकार सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी है। विधानसभा में घोटाले की सीबीआई जांच कराने का सर्वसम्मत निर्णय किया गया है। शिक्षा की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। पिछले दस वर्षों में सरकार ने एक भी नया शासकीय कालेज नहीं खोला है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति शोचनीय है। आम आदमी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेसी कुशासन के कारण दिल्ली की जो स्थिति बनी है, उसका चित्र संक्षेप में इस प्रकार है:

असुरक्षा

हर व्यक्ति असुरक्षित और भयभीत है। केन्द्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकार के आतंकवाद के प्रति नरम और ढुलमुल रवैये के चलते खुफिया एजेंसियों और पुलिस की पकड़ बहुत कमजोर हो गई है। न जाने कब और कहां बम ब्लास्ट हो जाए। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने पुलिस के मनोबल की क्षति की है। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकारी तन्त्र में तत्परता और एकजुटता का पूर्ण अभाव है। जनता के सहयोग की अनदेखी की

गई है।

कानून व्यवस्था का तो यह हाल है कि दिल्ली जुर्म की राजधानी मानी जाती है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब दिल्ली के किसी-न-किसी भाग में हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी जघन्य घटनाएं न होती हों। बलात्कार की निरन्तर हो रही घटनाओं ने महिलाओं के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। वरिष्ठ नागरिक सहमे-सहमें रहते हैं।

लोगों को न्याय नहीं मिलता। विभिन्न विभागों के कर्मियों को हफ्ता दिए बिना कोई अपना व्यवसाय और काम-धन्धा नहीं चला सकता। आम आदमी के लिए थाने में मामला दर्ज कराना कठिन है। दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होती। अदालतों में फौजदारी और दीवानी मामलों का लम्बे समय तक निपटारा नहीं होता।

दिल्ली की सड़कों पर चलना, चाहे गाड़ी में या पैदल, खतरे से खाली नहीं। दुर्घटनाओं की संख्या में भारी इजाफ़ा हुआ है। ब्लूलाईन बसों तथा बीआरटी से सम्बन्धित दुर्घटनाओं का कारण तो सीधे कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को राहत के प्रबन्ध अत्यन्त शिथिल और संवेदनहीन हैं।

दिल्ली सरकार का यह बहाना कि कानून और व्यवस्था का नियन्त्रण उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि तब यह प्रश्न उठता है कि दिल्ली में दोहरे शासन को हटाने के लिए कांग्रेस ने भाजपा का साथ क्यों नहीं दिया? दोहरे शासन के चलते भी अपनी पार्टी की केन्द्र सरकार के साथ यथोचित तालमेल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दिल्ली की निरन्तर गहराती असुरक्षा की परिस्थिति की जिम्मेदारी से दिल्ली सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती।

सीलिंग और तोड़फोड़

दिल्ली के असंख्य व्यवसायियों को सीलिंग व तोड़फोड़ का जो कहर झेलना पड़ा वह किसी भी महानगर के इतिहास में अद्वितीय है। मेहनतकश लोगों के कामकाज तबाह हो गए और उनके परिवारों की जीविका के साधन छिन गए। कुछ तो आत्महत्या के लिए विवश हो गए। यह सब इसलिए हुआ कि लैंडयूज़ में लचीलापन कांग्रेस के नज़रिये से मेल नहीं खाता। अपनी दकियानूसी विचारधारा के चलते कांग्रेस सरकार व्यापारियों-व्यवसायियों की रक्षा के लिए प्रावधान बनाने और जनता का पक्ष न्यायालय के सामने प्रभावी ढंग से रखने में पूर्णतः असफल रही। अब भी जो राहत मिली है, वह आधी-अधूरी है और अस्थायी है।

मंहगाई और आर्थिक दुरवस्था

निरन्तर बढ़ती मंहगाई का असर वैसे तो सबके जीवन स्तर पर पड़ा है, मगर इसकी मार विशेष रूप से गरीब वर्गों पर पड़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कई महीनों से मंहगाई दर 12 प्रतिशत के आस-पास रही है। जहां तक अनाज, दालों, खाद्य तेलों और रोजमर्रा की आवश्यक चीजों का सम्बन्ध है, मंहगाई दर इससे कहीं ज्यादा है। इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली के वितरणकारी (Distributive) व्यापार को, जिसके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, प्रोत्साहित करने के बजाय कमजोर किया है। दिल्ली में भण्डारण और गोदामों की व्यवस्था की अनदेखी की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लचर हालत में है

और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों तक सहायता नहीं पहुंच रही है। देश गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऋणों पर ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और दूध के दाम बार-बार बढ़ाए गए हैं। कर्मचारियों पर छंटनी का खतरा मंडरा रहा है। सेंसेक्स औंधे मुंह गिरा है। अर्थव्यवस्था जर्जर और अस्तव्यस्त है। संप्रग सरकार अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में पूर्णतः विफल रही है। सरकार को उपाय नहीं सूझ रहा।

विकास की बजाय नियन्त्रण

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग की केन्द्रीय सरकार के प्रयत्न से दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय खेलों के आयोजन का अवसर मिला है। यह महानगर के लिए विकास की ऊंची छलांग लगाने का मौका था, जिसका लाभ उठाकर मास्टर प्लान की सभी अड़चनों को दूर किया जा सकता था, अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जा सकता था, पुनर्वास बस्तियों में मालिकाना हक दिए जा सकते थे और दिल्ली के बहुआयामी विकास का परिप्रेक्ष्य निर्धारित किया जा सकता था ताकि सरकारी तन्त्र, उद्यमी और आम लोग अपने-अपने ढंग से विकास में भागीदार बनते। लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को हाथ से फिसलने दिया है। विकास के नाम पर कुछ छुटपुट प्रोजेक्टों का निर्माण किया गया है। दिल्ली का वातावरण आज ऐसा है कि यदि कोई कुछ भी सकारात्मक करना चाहे तो उसे झेलना पड़ता है अनिश्चितताओं, बन्दिशों और रिश्वत का अंबार।

हमारे संकल्प

लोकसभा चुनावों के पूर्व होने वाले छः राज्यों के चुनावों के अवसर पर देशवासियों को भाजपा और उसके नेतृत्व वाली राजग सरकारों के कार्यों की कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के कार्यों से तुलना करना तर्कसंगत होगा। भाजपा और राजग की सरकारें अपने सुशासन के लिए प्रसिद्ध हैं तो कांग्रेस सरकारें अपने कुशासन के लिए बदनाम।

दिल्ली के गौरव की रक्षा

भाजपा दिल्ली का सर्वांगीण विकास करेगी ताकि यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगरों से प्रतिस्पर्धा कर सके। दिल्ली की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत की रक्षा की जाएगी।

दिल्ली लघु भारत है। इसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग अपनी-अपनी भाषा और प्रादेशिक संस्कृति को संजो कर निवास करते हैं। उनकी भाषा, संस्कृति और प्रादेशिकता की रक्षा की जाएगी और उन्हें पूर्ण सम्मान दिया जाएगा।

कुशल, पारदर्शी, जनकल्याणकारी और जवाबदेह प्रशासन

प्रशासन को कुशल, पारदर्शी, जनकल्याणकारी और जवाबदेह बनाया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में जनसहभाग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए वार्ड/विधानसभा क्षेत्र पर समितियों का गठन किया जाएगा जिनमें आर.डब्ल्यू.ए (RWA) को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अप्रासंगिक हो गए कानूनों को समाप्त किया जाएगा। लाइसेंस,

परमिट और इंसपेक्टरी राज से राहत दिलाई जाएगी।

पूर्ण राज्य का दर्जा

बहुस्तरीय और बहुसंस्थागत ढांचे के कारण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को और दिल्लीवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की कांग्रेस ने पूर्ण उपेक्षा की है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पूर्ण राज्य के सवाल पर गोलमोल वक्तव्य देने और अपनी असफलता की सफाई देने में लगी हैं। भाजपा दिल्ली को अधिकार सम्पन्न पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी और बहुस्तरीय जटिल प्रशासनिक ढांचे को एकीकृत सरल ढांचे में बदलेगी।

आतंकवाद और सुरक्षा

- अवैध घुसपैठ हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी बोझ है। भाजपा अवैध घुसपैठ को कड़ाई से रोकेगी। अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों को पहचान कर वापस भेजा जाएगा। नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने और बहुउद्देश्यीय पहचान पत्र जारी करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली पहल करेगी।
- अफजल गुरु को फांसी देने का न्यायालय का निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। भाजपा न्यायालय का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करेगी।
- पुलिस और गुप्तचर एजेंसी को चुस्त-दुरुस्त किया

जाएगा और उसे तकनीकी दृष्टि से सुसज्ज किया जाएगा।

- आतंकवाद के कारण जान-माल की क्षति होने पर क्षति की भरपाई की जाएगी।

बुनियादी सुविधाएं

भाजपा संकल्प करती है कि दिल्ली को साफ-सुथरा नगर बनाया जाएगा। बिजली, पानी, सीवरेज, परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी और आधारभूत ढांचे को उन्नत किया जाएगा।

बिजली

- दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण के परिणामस्वरूप हुए सरकारी घाटे की जांच कराई जाएगी।
- बिजली कम्पनियों के साथ करार की समीक्षा की जाएगी; एकाधिकार समाप्त किया जाएगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- दिल्लीवासियों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी।
- एन.टी.पी.सी. और बिजली उत्पादन करने वाली अन्य कम्पनियों और राज्यों के साथ मिलकर नए संयंत्र लगाए जायेंगे ताकि दिल्ली की आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सके; गैस आधारित बवाना और इन्द्रप्रस्थ संयंत्र प्रारम्भ किए जाएंगे।
- बिजली के तेज चलने वाले मीटरों को बदला

जाएगा। तेज मीटरों के कारण गलत रूप में वसूली गई राशि वापस की जाएगी और उपभोक्ता शिकायतों को शीघ्र निपटाने का तन्त्र मजबूत किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में स्वतन्त्र और निष्पक्ष 'फास्ट ट्रैक उपभोक्ता शिकायत निवारण तन्त्र' गठित किया जाएगा।

- गैर परम्परागत ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- स्टीट लाइट की व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाया जाएगा।

पानी

भाजपा समुचित मात्रा में उचित गुणवत्ता वाले पेयजल को नागरिकों का मूलभूत अधिकार मानती है। हर नागरिक को पेयजल की नियत मात्रा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

- कांग्रेस अपने 10 वर्षों के शासन के दौरान 900 एम.जी.डी. पानी का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है। भाजपा दिल्ली को 1000 एम.जी.डी. पानी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सोनिया विहार, नांगलोई और बवाना जल संयंत्रों को पूरी तरह चालू किया जाएगा, द्वारका और ओखला में नए जल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हैदरपुर, भागीरथी, वजीराबाद और सोनिया विहार के मौजूदा संयंत्रों के स्थल पर रिसाईक्लिंग संयंत्र स्थापित कर तथा बाहर से कच्चा पानी प्राप्त कर पानी की उपलब्धता में भारी वृद्धि की जाएगी।
- वर्षा जल संरक्षण के कारगर उपाय किए जाएंगे; नए

- जलाशय निर्मित किए जाएंगे और पुराने जलाशयों का संवर्धन किया जाएगा
- सभी अनधिकृत कालोनियों और ग्रामीण इलाकों को पाइप से पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी।
 - आर.डब्ल्यू.ए. के सहयोग से जल का संरक्षण किया जाएगा।
 - पुरानी पाइप लाइनों को बदला जाएगा।

सीवरेज

- पूरी दिल्ली को सीवरेज नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- मौजूदा सीवेज संयंत्रों की शोधन क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए शोधन संयंत्र लगाए जायेंगे।
- बिना शोधन के सीवेज नदी में न जाये, इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- मुख्य पार्कों और बागों में शोधित effluent का उपयोग करने के लिए अलग से पाइप बिछाए जाएंगे।
- गांवों और अनधिकृत कालोनियों में मिनी सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और शोधित effluent का स्थानीय स्तर पर सिंचाई, बागबानी के लिए उपयोग किया जाएगा।

परिवहन व्यवस्था

- दिल्ली के लिए अधिकार सम्पन्न एकीकृत परिवहन प्राधिकरण (Unified Transport Authority) गठित

किया जाएगा।

- बी.आर.टी. कॉरिडोर की समीक्षा की जाएगी।
- मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और अगले फेज़ को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के सहयोग से बहुमंजिले और भूमिगत पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।
- दिल्ली की बड़ी व छोटी सड़कों का सुधार किया जाएगा।
- दोनों रिंग रोडों के छूटे हुए हिस्से पूरे किए जाएंगे और एक और (तीसरा) रिंग रोड बनाया जाएगा।
- रिंग रेल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने का सुझाव भारत सरकार को दिया जाएगा।
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कारगर उपाय किए जाएंगे।
- बसों के बेड़े को दुगना किया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत आधुनिक बसें चलाई जाएंगी।
- रेलवे लेवल क्रॉसिंग समाप्त किए जाएंगे।
- एक ही टिकट से बस और मेट्रो से यात्रा करने की व्यवस्था की जाएगी

पुनर्वास कालोनियां

सभी पुनर्वास कालोनियों को मालिकाना हक दिया जाएगा और समयबद्ध तरीके से मालिकाना दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्वास्थ्य

दिल्ली की आबादी इस समय 1.75 करोड़ है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों के लोग भी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जितना दबाव है, उसकी तुलना में सेवाएं कम उपलब्ध हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। भाजपा अपने को इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संकल्पित करती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रति हजार व्यक्ति पर 5 बैड उपलब्ध होने चाहिए। इस समय दिल्ली में प्रति हजार व्यक्ति दो बैड उपलब्ध हैं। बैडों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- आज अस्पतालों में कुशल श्रम शक्ति, नर्सों एवं प्रशिक्षित डाक्टरों की भारी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए भाजपा नए नर्सिंग ट्रेनिंग कालेज, पैरामैडीकल कोर्सेस की शिक्षा के संस्थान खोलेगी।
- नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे और पूरक व्यवस्था के रूप में मैडीकल इन्श्योरेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गरीबी रेखा के नीचे के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भागीदारी का उचित अवसर मिलेगा।
- मंहगे ऐलोपैथिक इलाज का बोझ सब लोग, खासतौर से कमजोर वर्ग, बर्दाश्त नहीं कर पाते। भाजपा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद,

- यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक को भी ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ बढ़ावा देगी।
- प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी हकीम अजमलखाँ द्वारा स्थापित तिब्बिया कालेज को विश्वविद्यालय स्तर का दर्जा प्रदान किया जाएगा ताकि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा और अनुसन्धान को बढ़ावा मिल सके।
 - दिल्ली में रहने वाले गरीबों, झुग्गी झोंपड़ी और स्लम बस्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में मोबाइल डिस्पेंसरियों की व्यवस्था की जाएगी।
 - दिल्ली में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए पी.सी.आर. को एम्बुलेंस की सुविधाओं से सुसज्ज किया जाएगा और कैट व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
 - पोलियो, एड्स, हैपीटाइटिस ए.बी.सी.के टीकाकरण का तथा रोगों की रोकथाम का कार्यक्रम व्यापक जनअभियान के रूप में चलाया जाएगा।
 - खाद्य वस्तुओं और दवाओं में मिलावट को सख्ती से रोका जाएगा।
 - 2014 तक मलेरिया और डेंगू का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा।

शिक्षा

शिक्षा मानव विकास और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा के विस्तार और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि दिल्ली को नॉलेज (Knowledge) राजधानी बनाया जा सके।

- उच्च शिक्षा की लगातार बढ़ रही मांग के मद्देनजर नए विश्वविद्यालय और कालेज खोले जाएंगे।
- शिक्षा संस्थाओं और छात्रावासों के लिए रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्कूलों में प्रवेश के मौजूदा दोषपूर्ण नियमों में सुधार किया जाएगा और बच्चों को पड़ोस के स्कूल में प्रवेश की गारंटी दी जाएगी
- दिल्ली के सभी स्कूलों की देख-रेख के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों की परामर्श समितियां बनाई जाएंगी।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'प्रतिभा विकास विद्यालय' खोले जाएंगे ताकि आम नागरिकों के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें।
- प्रत्येक वार्ड में कम-से-कम एक कम्पोजिट विद्यालय खोला जाएगा।
- दिल्ली के स्कूलों में भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित तथा नैतिक शिक्षा और योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पुस्तकालयों और वाचनालयों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- खेल और योग शिक्षण को स्कूली स्तर पर शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाएगा।
- स्कूली पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दिल्ली स्टेट बुक कारपोरेशन की स्थापना की जाएगी।
- मिड-डे मील की गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा और स्वयं सहायता गुप्तों की सहायता से इस कार्यक्रम पर नजर रखी जाएगी।
- शिक्षा के अधिकार को व्यवहार में उतारा जाएगा; 6

से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर को न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा; दिल्ली की साक्षरता दर शत प्रतिशत की जाएगी।

- यमुनापार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कैम्पस बनाया जाएगा।
- विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों तथा स्कूली शिक्षकों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाएगा।
- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाएगी।
- अध्यापकों के रिक्त पड़े सभी पद भरे जाएंगे।
- अधिक-से-अधिक बच्चों को, अच्छी-से-अच्छी और सस्ती शिक्षा देना शैक्षिक प्रयासों का लक्ष्य होगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों के शैक्षिक वातावरण को मजबूत करने की विस्तृत योजना बनाई जाएगी।
- शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम-से-कम एक तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा जिसमें ड्राइविंग, बिजली फिटिंग, प्लम्बिंग, सीवर एवं पाईप फिटिंग जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मेट्रो और बसों के यात्रा किराए में छात्रों को रियायत दी जाएगी।

मास्टर प्लान

दिल्ली नगर निगम के 2007 के चुनावों के ठीक पहले राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर तीसरा मास्टर प्लान

आनन-फानन में जारी कर दिया गया। जमीनी हकीकत से कटे हुए तीसरे मास्टर प्लान में अनेक असंगतियां और विसंगतियां रहना स्वाभाविक था। परिणामतः मास्टर प्लान जारी करने के बाद उसमें अनेक संशोधन करने पड़े और दिल्लीवासियों को सीलिंग और तोड़फोड़ के कहर से गुजरना पड़ा। आज भी सीलिंग व तोड़फोड़ की तलवार लोगों पर लटक रही हैं।

भाजपा मास्टर प्लान-2021 की विसंगतियों को दूर करेगी, दिल्ली की जमीनी हकीकत के अनुरूप इसमें आवश्यक और उचित संशोधन करेगी और दिल्लीवासियों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूँढेगी।

नियमितीकरण

- वन टाईम ऐमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी।
- अवैध निर्माण के नियमितीकरण को सरल, सहज और व्यावहारिक बनाया जाएगा।
- बिना पुनर्वास के किसी का आवास और रोटी-रोजी का जरिया उजाड़ा नहीं जाएगा।
- रिहैबिलिटेशन, रिसैटलमेंट और अनधिकृत कालोनियों में 3 फुट तक के छज्जों को नियमित किया जाएगा।
- कटरों का पुनर्विकास किया जाएगा।

अनधिकृत कालोनियां

दिल्ली में जब कभी भी अनधिकृत कालोनियां नियमित की गई हैं, जनसंघ-भाजपा के शासनकाल में ही की गई हैं। कांग्रेस ने

समय-समय पर बेसिरपैर की घोषणाएं कर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करने का नाटक कर अनधिकृत कालोनियों के लोगों को ठगा है और कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न कानूनी अड़चनों को दूर किया गया और न ही इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं। कांग्रेसी शासन के दस वर्ष बीत जाने पर भी ये कालोनियां नियमित नहीं की जा सकी हैं।

भाजपा अनधिकृत कालोनियों को नियमित करेगी; इनके लिए स्वयं सरकार ले-आउट प्लान एवं अन्य कागजात तैयार करेगी। सम्बन्धित विभागों में डायरेक्टोरेट ऑफ रैगुलेराइजेशन गठित किए जायेंगे।

यमुनापार का विकास

- यमुनापार के विकास के लिए दिल्ली में भाजपा शासन के दौरान यमुनापार विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यमुनापार क्षेत्र में, जिसमें दिल्ली की लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है, बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा सके और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
- दिल्ली नगर निगम के पुनर्गठन के अंग के रूप में यमुनापार के लिए अलग से नगर निगम बनाया जाएगा।

श्रमिक

- श्रमिकों की मजदूरी/वेतन को कीमत सूचकांक से जोड़ा जाएगा।

- संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा तथा उनके कल्याण के उपाय किए जाएंगे।
- श्रम विवादों को त्वरित निपटाया जा सके, इसके लिए विवाद निपटाने के तंत्र को चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा।
- छटनी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्र

- भूमि सुधार अधिनियम (DLR Act) में उचित संशोधन किया जाएगा और उसके किसान विरोधी प्रावधानों को, विशेषरूप से धारा 81 को और 8 स्टैण्डर्ड एकड़ के प्रावधान को निरस्त किया जाएगा।
- किसानों की जमीन अधिग्रहण मुआवजा राशि बढ़ाकर कम से कम दो करोड़ रु. प्रति एकड़ की जाएगी और उसमें हर वर्ष उचित वृद्धि की जाएगी। भू-स्वामी को अधिकार होगा कि या तो वह मुआवजे की राशि स्वीकार कर ले या विकसित भूमि का एक भाग।
- सीमावर्ती गांवों को पूर्णतया 'ग्रीन' रखने का मास्टर प्लान का प्रावधान न तो न्यायसंगत है और न ही व्यावहारिक। उन गांवों में एक एकड़ से बड़े भूभागों पर फार्म हाउस की इजाजत दी जाएगी। उन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों की भी अनुमति होगी।
- जिस भूमि पर खेती हो रही है, उसमें ट्यूबवैल के लिए बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा।

- लाल डोरा का विस्तार किया जाएगा और उसके ले-आउट की योजना उच्चस्तरीय शहरी स्तर पर होगी।

कमजोर वर्ग

- दिल्ली जैसे महानगर की स्थिति को ध्यान में रख गरीबी रेखा (बीपीएल) की परिभाषा में परिवर्तन किया जाएगा।
- गरीब लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गरीब लोगों को राशन कार्ड प्राप्त हो।
- रेहड़ी-पटरी, खोमचा, मोची, नाई, धोबी आदि छोटे-छोटे काम-धन्धा करने वाले वर्गों के लिए रोजगार स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए सस्ती बीमा योजना उपलब्ध कराई जाएगी।
- गरीब बस्तियों के निकट जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

आवास नीति

- शहरी गरीब लोग अनधिकृत बस्तियों; पुनर्वास बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टरों में रहते हैं। इनके लिए सरकार की कोई दूरगामी आवास नीति नहीं है। भाजपा शहरी गरीब वर्ग के आवास

अधिकार को महत्वपूर्ण मानती है और इसके लिए दीर्घकालिक आवास नीति बनाएगी। भाजपा शहरी गरीब वर्गों और घरों में सेवाएं प्रदान करने वाले वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का कार्यक्रम प्रारम्भ करेगी। यह कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चलाया जाएगा।

- मध्य आय वर्ग को उचित दाम पर सरकारी क्षेत्र से आवास नहीं मिल पाता। मध्य वर्ग के लिए सरकारी एजेंसियों और सहकारी सोसायटियों तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।
- दिल्ली सरकार के कर्मचारियों, दिल्ली पुलिसकर्मियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सरकारी एजेंसी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आवास बनाकर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- डीडीए फ्लैट्स के पुनर्निर्माण की इजाजत दी जाएगी ताकि उन्हें ग्रुप हाउसिंग के समकक्ष बड़े हुए एफ.ए. आर. का लाभ मिल सके।
- फुटपाथ पर सोने वालों के लिए आश्रय स्थल/रैन बसेरे बनाए जाएंगे।

सहकारिता

- सहकारी आंदोलन को नई गति दी जाएगी और नए सहकारी कानून की कमियों को दूर किया जाएगा
- ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार

को कड़ाई से समाप्त किया जाएगा और इन सहकारी समितियों के सदस्यों को व्यावाहरिक योजना बनाकर समय बद्ध तरीके से फ्लैटो का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा।

व्यापार

- दिल्ली के वितरणकारी स्वरूप (Distributive Character) को मजबूत किया जाएगा।
- पृथक् वाणिज्य विभाग स्थापित किया जाएगा।
- व्यापार और वाणिज्य को अफसरशाही और नौकरशाही के अनुचित हस्तक्षेप से निजात दिलाई जाएगी।
- व्यापार-वाणिज्य सम्बन्धी अप्रासंगिक हो गए कानूनों को समाप्त किया जाएगा।
- कर के स्वैच्छिक आकलन की सीमा बढ़ाई जाएगी।
- अनिवार्य पंजीकरण की सीमा बढ़ाई जाएगी।
- व्यापारियों के लिए कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा।

मीडियाकर्मियों को सुविधाएं

स्वतन्त्र मीडिया लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह लोक शिक्षण का और लोक चेतना जगाने का प्रबल माध्यम है।

- दिल्ली के पत्रकारों के लिए अलग से इन्द्रप्रस्थ प्रेस क्लब का निर्माण किया जाएगा।
- पत्रकारों को मान्यता देने के लिए एक सरल नीति बनाई जाएगी।
- दिल्ली के पत्रकारों को सरकार द्वारा बनाए गए

- मकानों में आरक्षण दिया जाएगा ।
- दिल्ली में एक अतिआधुनिक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा ।

उद्योग

कांग्रेस सरकार ने उद्योगों की घोर उपेक्षा की है। भाजपा उद्योग जगत की आवश्यकताओं को सहानुभूतिपूर्वक पूरा करेगी ।

- उद्योगों के पुनर्विकास के लिए तथा हाईटैक उद्योगों, बायोटेक्नालजी और आई.टी.जैसे गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे ।
- औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे को समुन्नत किया जाएगा और इन क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।
- लघु उद्योगों और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
- दिल्ली जैसे महानगर में लोगों को मोटर गाड़ी, एयरकंडीशनर, टीवी आदि घरेलू उपयोग की वस्तुओं की मरम्मत और रखरखाव सेवाओं की बराबर जरूरत पड़ती रहती है, पर दिल्ली की विकास योजना में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया । भाजपा रखरखाव सेवाओं सम्बन्धी उद्योगों के लिए उचित प्रावधान करेगी ।
- औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और कम से कम पांच वर्ष के लाइसेंस दिए जाएंगे; दोहरी लाइसेंस पद्धति समाप्त की जाएगी ।

प्रदूषण नियन्त्रण और यमुना का शुद्धीकरण

दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के बारे में कांग्रेस के दस वर्षों का शासनकाल निराशापूर्ण रहा है। आज दिल्ली दुनिया के 10 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है और देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। भाजपा दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए गम्भीर प्रयास करेगी।

- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदूषण की स्थिति पर सतत नजर रखने के लिए एक निकाय गठित किया जाएगा।
- प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मामलों में निर्णय करने में नौकरशाहों के स्थान पर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई जाएगी
- दिल्ली के मौजूदा 18 प्रतिशत 'ग्रीन कवर' को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा।
- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विस्तार कर वाहन प्रदूषण को कम किया जाएगा।

यमुना का दिल्ली के जनजीवन के लिए असंदिग्ध महत्व है। किन्तु कांग्रेस शासन की लापरवाही के कारण यमुना जैसी पावन नदी गंदा नाला बनकर रह गई है। कांग्रेस ने विगत दस वर्षों में यमुना के शुद्धीकरण की घोर उपेक्षा की है। भाजपा यमुना के शुद्धीकरण और यमुनातट के सौन्दर्यीकरण के काम को प्राथमिकता और गम्भीरता से करेगी। यमुना तटों का व्यवसायीकरण नहीं होने दिया जाएगा।

यमुना में गंदे नालों को गिरने से रोका जाएगा और केवल शोधित अवजल को नदी में गिरने दिया जाएगा। गंदे नालों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा; यमुना के तटों को अत्यन्त सुन्दर

बनाया जाएगा, वहां पर खेल मैदान, सैरगाह, जलीय खेलों, नौका विहार आदि का प्रबन्ध किया जाएगा; तट के दोनों ओर लम्बी सड़कें और फुटपाथ बनाए जाएंगे।

संस्कृति और खेल

- प्रत्येक जिले में पुस्तकालय, सांस्कृतिक केन्द्र और खेलकूद परिसर खोले जाएंगे। सांस्कृतिक-सामाजिक कार्यों के लिए नए सभागार बनाए जाएंगे, जिनका शुल्क बहुत मामूली होगा। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा और खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 1998 में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने रोहतक रोड पर खेलकूद विद्यालय का शिलान्यास किया था। कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में यह प्रोजेक्ट जहां का तहां रुका पड़ा है। भाजपा इसे पूरा करेगी।
- दिल्ली खेल अकादमी बनाई जाएगी।
- पुरस्कृत खिलाड़ियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।
- दिल्ली के कामनवेल्थ खेलों के पदक विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
- लोक कलाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- हिन्दी, पंजाबी, उर्दू और सिंधी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ अन्य भाषाओं विशेषरूप से आंचलिक भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा।

- दिल्ली में पंजाबी को द्वितीय भाषा का स्थान देने के निर्णय को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।
- बालकों के मनोरंजन और संस्कार के लिए आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न बाल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- दिल्ली की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए दिल्ली म्यूजियम स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रमंडलीय खेल

खेल के क्षेत्र में श्री विजय कुमार मल्होत्रा का दीर्घ और व्यापक अनुभव है। वह खेल से जुड़े अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। विगत में भी वह खेलों से जुड़े संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। खेल जगत का उनका व्यापक अनुभव 2010 में दिल्ली में होने वाली राष्ट्रमंडलीय खेलों के आयोजन को सफल नेतृत्व प्रदान करेगा।

राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन दिल्ली के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। ये खेल दिल्ली के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और दिल्ली के विकास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का अवसर देते हैं। भाजपा इस अवसर का पूरा लाभ उठाएगी और राष्ट्रमंडलीय खेलों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का निर्माण समयबद्ध तरीके से करेगी।

युवा एवं रोजगार

- निर्जीव पड़े राज्य वित्त निगम को सक्रिय किया

- जाएगा और उसके माध्यम से स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- लघु उद्योग लगाने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।
 - आई.टी. इंडस्ट्री जैसे हाईटेक उद्योगों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ताकि इसमें युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

विभिन्न वर्गों का सामाजिक - आर्थिक कल्याण

महिलाएं

- महिला आयोग को सशक्त और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि वह महिलाओं के प्रति भेदभाव मिटाने और महिलाओं का सशक्तिकरण करने के दायित्व को प्रभावी तरीके से कर सकें।
- महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा।
- बलात्कारियों को कठोर-से-कठोर सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
- उत्पीड़ित महिलाओं को जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित किए जाएंगे।
- कामकाजी एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए आवासीय होस्टलों का निर्माण किया जाएगा।
- सस्ती क्रैच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिक

- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की जाएंगी।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामूहिक आवासीय केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों और सेवा निवृत्त पुलिस/सशस्त्र सेना कर्मियों को रियायती बस-मैट्रो रेल पास जारी किए जाएंगे।

सिन्धी समाज

दिल्ली में लगभग 5 लाख सिन्धी रहते हैं। देश विभाजन के परिणामस्वरूप विस्थापित होकर ये भारत के विभिन्न नगरों में रह रहे हैं। इनका अपना कोई प्रदेश नहीं है। भाजपा प्रयास करेगी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 के अन्तर्गत एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए जो सिन्धियों से सम्बन्धित सभी मामलों की देखरेख करे।

विस्थापित कश्मीरी

विस्थापित कश्मीरी परिवारों के पुनर्वास और उनकी शैक्षिक तथा रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जाति विकास वित्त निगम को सक्रिय

किया जाएगा और अनुसूचित वर्गों को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरल-सुगम नीति बनाई जाएगी।
- परम्परागत निजी व्यवसायों को लघु/घरेलू उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा और सभी प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
- जाति प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाएगा।
- अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- मकान बनाने/कन्या का विवाह करने के लिए अनुदान एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के नौकरियों तथा शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

अल्पसंख्यक

- मदरसों की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम को चुस्त दुरुस्त और प्रभावी बनाया जाएगा।

विकलांग

- शारीरिक विकलांगों को आवश्यकतानुसार मुफ्त

- कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे।
- ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
- यथायोग्य स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड योजना लागू की जाएगी।
- विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- भवन निर्माण को विकलांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- आटोइज्म, स्पास्टिक्स और मानसिक विकलांगताग्रस्त लोगों की शिक्षा और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- मेट्रो रेल से यात्रा के किराए में रियायत दी जाएगी।

1984 के दंगों के अपराधियों को सजा

लगभग 25 वर्ष होने को आए पर अभी तक 1984 के सिख-विरोधी दंगों के अपराधियों को सजा नहीं दी जा सकी है। भाजपा प्रयत्न करेगी कि 1984 के दंगों के अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा।

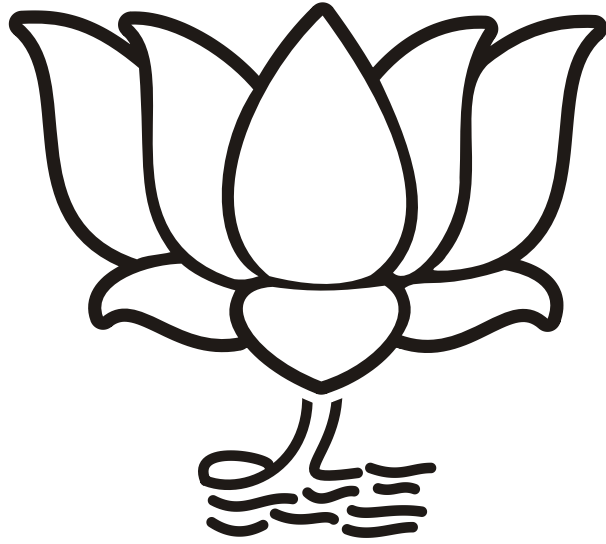
आशाभरा उज्ज्वल भविष्य

जनता की शक्ति के बल पर ही लोकतन्त्र में सरकार बनती है। किन्तु पिछले एक दशक से दिल्ली के नागरिक अपने को लाचार महसूस करते आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी आकांक्षाओं की निर्दयतापूर्वक उपेक्षा की है। कर के रूप में जनता

से बटोरा गया धन सनकभरी स्कीमों पर खर्च किया गया। कांग्रेस का 10 वर्ष का शासन ऐसे शासन के रूप में याद किया जाएगा जिसमें लोगों को न जीवन की सुरक्षा प्राप्त हुई और न आर्थिक न्याय, बेहतर भविष्य की अनुभूति होना तो दूर की बात है। अब परखे हुए कुशल प्रशासक प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में दिल्ली उज्ज्वल भविष्य की आशा कर सकती है और दिल्लीवासी गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाकर चल सकते हैं। भाजपा के शासन का अर्थ होगा सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी, बेखौफ चलने के लिए चौड़ी सड़कें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बढ़िया स्कूल और कालेज, प्रदूषणमुक्त वातावरण में स्फूर्ति अनुभव करने के लिए पवित्र यमुना नदी और अंधेरे से निजात पाने के लिए बिजली की अबाध आपूर्ति, ई-गवर्ननेंस का अधिकाधिक प्रयोग और इंस्पेक्टरीराज से छुटकारा, भ्रष्टाचार के स्थान पर पारदर्शिता, माताओं, बहनों, बेटियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेखौफ जीने हेतु सुरक्षा का वातावरण। ऐसे शासन के लिए आइये हम सब मिलकर 29 नवम्बर को दिल्ली में 10 वर्ष के कांग्रेसी कुशासन का अंत करें और एक नए आशा भरे दशक की शुरुआत। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना कीमती मत भाजपा और उसके चुनाव चिन्ह 'कमल' के पक्ष में दें।

★★★★★

महंगी पड़ी कांग्रेस
अब चाहिए राहत

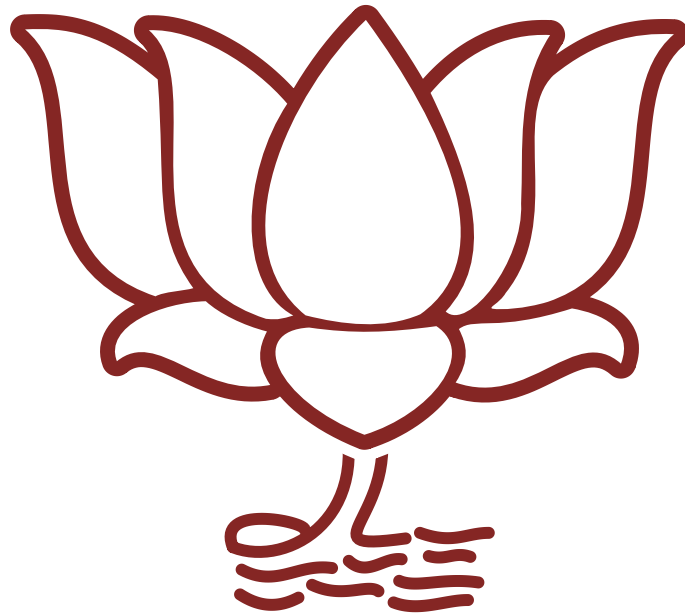


BJP

बेहतर भविष्य के लिए
भाजपा को वोट दें

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव : 2008
चुनाव घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु



आशा भरे उज्ज्वल भविष्य के लिए
भाजपा को वोट दें

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली

हमारा संकल्प

29 नवम्बर, 2008 को दिल्ली की 1.75 करोड़ जनता को कांग्रेस के एक दशक के दिशाहीन और भ्रष्ट शासन से निजात पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।

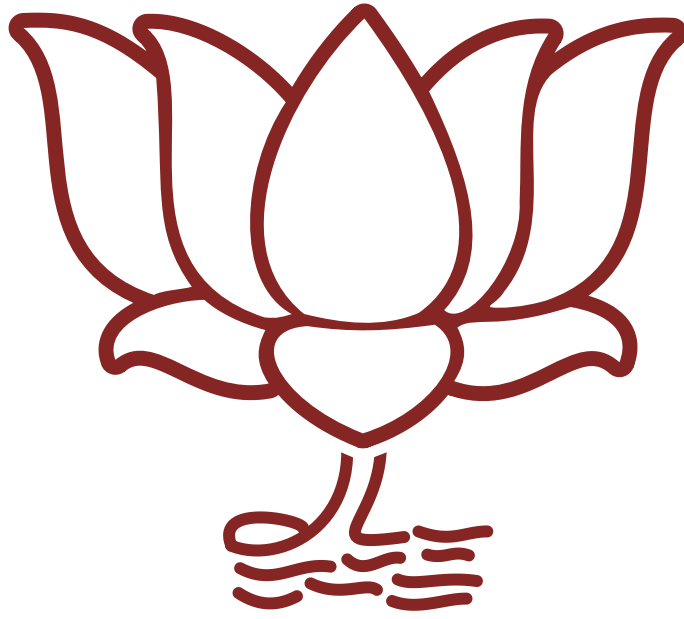
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को वचन देती है कि सत्ता में आने पर वह दिल्ली को विश्वस्तरीय महानगर बनाएगी जिसमें सभी वर्गों, क्षेत्रों और प्रदेशों के लोगों को सद्भाव और सौहार्दपूर्वक रहने और प्रगति करने का समान अवसर उपलब्ध होगा। और यह परिवर्तन होगा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में जिनका राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र का लम्बा अनुभव, बेदाग व्यक्तित्व, प्रशासनिक कौशल, विराट संसदीय अनुभव किसी के लिए भी ईर्ष्या की बात हो सकती है। श्री मल्होत्रा के मुख्य कार्यकारी पार्षद (1967-72) का कार्यकाल दिल्ली के विकास का स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है। इस काल में बहुमुखी और सर्वांगीण विकास की नींव रखी गई। पहली बार फ्लाईओवर बने, भूमिगत मार्ग बने, 18 कालेज खोले गए, यमुना तटों को सुंदर और हरा-भरा बनाया गया, भूमिहीनों को भूमि दी गई, नए अस्पताल और डिस्पेंसरियां खोली गईं और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर नगर बनाया गया। प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया, हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोला गया, गलियों में ईंटों के खड्डों और नालियां बनाई गईं, 4 हजार कटरों में फ्लश की टट्टियां बनीं और वहां के निवासियों को शुद्ध जल तथा बिजली प्रदान की गई।

भाजपा दिल्लीवासियों को आशा भरे उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन देती है। भाजपा संकल्प करती है कि :

1. राजधानी दिल्ली को विश्व का श्रेष्ठ, सुन्दर, स्वच्छ एवं हरा-भरा नगर बनाया जाएगा।
2. दिल्ली में रहने वाले सभी भाषा-भाषियों की भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, त्यौहारों को महत्व दिया जाएगा और उनके लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
3. भय, भूख और भ्रष्टाचार को समाप्त कर ईमानदार, कुशल प्रशासन दिया जाएगा।
4. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
5. दिल्ली में प्रतिवर्ष निम्न मध्यम वर्ग व मध्यम वर्ग के लिए एक लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र की सहायता ली जाएगी।
6. सभी अनधिकृत कालोनियों को वैध किया जाएगा और वहां नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी।
7. दिल्ली में आममाफी योजना के अन्तर्गत मकानों व दुकानों में अब तक बने अनधिकृत निर्माण को नियमित किया जाएगा।
8. सभी झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को वहीं पर या उसके निकट फ्लैट या प्लॉट दिए जाएंगे।
9. मंहगाई को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
10. सभी गरीबों को राशन के कूपन दिए जाएंगे जिनसे किसी भी दुकान से राशन सस्ते दामों पर खरीद सकें।
11. दिल्ली में पानी-बिजली की कमी को दूर किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में शुद्ध पानी का प्रबन्ध किया जाएगा।
12. तेज भागते मीटरों को बदलने के लिए कम्पनियों को मजबूर किया जाएगा।
13. यमुना नदी में गंदे नाले को गिरने से रोका जाएगा और यमुना नदी को साफ, स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाया जाएगा।
14. आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे।
15. आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए केन्द्र पर दबाव डाला जाएगा।
16. अफजल गुरु की फांसी की फाईल जिसे शीला दीक्षित जी ने दबा रखा है तुरन्त केन्द्र को भेजी जाएगी।

17. किसानों को भूमि का मुआवजा बाजार दर पर दिया जाएगा।
18. दिल्ली में 50 नए कालेज खोले जायेंगे ताकि 12वीं पास सभी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सके।
19. दिल्ली में बड़े अस्पतालों के साथ नए मेडीकल कालेज खोले जायेंगे।
20. दिल्ली में अस्पतालों में 10,000 नए बिस्तरों का विस्तार किया जाएगा।
21. प्रत्येक निगम क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी, एक जिम, एक कम्युनिटी सेंटर, एक ओरनामेंटल पार्क बनाया जाएगा।
22. मेट्रो रेलवे का विस्तार किया जाएगा और रिंग रेलवे के साथ-साथ स्काई ट्राम योजना प्रारम्भ की जाएगी।
23. यातायात में लगने वाले ट्रेफिक जामों को रोका जाएगा और एक उत्कृष्ट परिवहन व यातायात योजना बनाई जाएगी।
24. निजी क्षेत्र के सहयोग से बहुमंजिले और भूमिगत पार्किंग स्थल बनाए जायेंगे।
25. पुनर्वास कालोनियों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
26. शिक्षकों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाएगा और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाएगी।
27. रेहड़ी-पटरी, खोमचा, नाई, धोबी आदि छोटे-छोटे काम-धन्धा करने वाले असंगठित वर्गों को रोजगार स्थल उपलब्ध कराए जायेंगे।
28. दिल्ली के पत्रकारों के लिए इन्द्रप्रस्थ क्लब का निर्माण किया जाएगा और एक अति आधुनिक मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा।
29. अवैध घुसपैठ को कड़ाई से रोका जाएगा और अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को पहचान कर वापस भेजा जाएगा।
30. दिल्ली अपराधों की राजधानी बन गयी है। अपराधों की रोकथाम और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
31. बी.आर.टी. कॉरिडोर की समीक्षा की जाएगी।
32. बसों के बेड़े को दुगना किया जाएगा और पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत आधुनिक बसें चलाई जाएंगी।
33. वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं के पूरक के रूप में मेडीकल इन्श्योरेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
34. खाद्य वस्तुओं और दवाओं में मिलावट को सख्ती से रोका जाएगा।
35. दिल्ली में पुस्तकालयों और वाचनालयों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
36. मास्टर प्लान की विसंगतियों को दूर किया जाएगा और उसे दिल्ली की जमीनी हकीकत के अनुरूप ढाला जाएगा।
37. व्यापार की दृष्टि से दिल्ली के वितरणकारी स्वरूप (Distributive Character) को मजबूत किया जाएगा।
38. दिल्ली में पंजाबी को द्वितीय भाषा का स्थान देने के निर्णय को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
39. 1984 के सिख विरोधी दंगों के अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी।
40. बालकों के मनोरंजन और संस्कार के लिए बाल केन्द्र खोले जाएंगे।
41. महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किए जायेंगे।

महंगी पड़ी कांग्रेस
अब चाहिए रहत



BJP

बेहतर भविष्य के लिए
भाजपा को वोट दें